भारत - मॉरीशस संबंध

भारत और मॉरीशस के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए। मॉरीशस ने डच, फ्रांस और ब्रिटिश कब्जा के दौरान भी भारत के साथ संपर्क बनाए रखा।

1820 के दशक से भारतीय मजदूरों ने गन्ने के खेतों पर काम करने के लिए मॉरीशस आना शुरू कर दिया। 1834 से, जब ब्रिटिश संसद द्वारा दासता का उन्मूलन कर दिया गया, संविदा श्रमिक के रूप में भारी संख्या में भारतीय मजदूरों को मॉरीशस लाया जाने लगा। 2 नवंबर, 1834 वह दिन है जब एटलस जहाज मॉरीशस पहुंचा जिस पर भारतीय संविदा श्रमिकों की पहली खेप थी। इस दिन को अब मॉरीशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुल मिलाकर, एक अनुमान के अनुसार लगभग आधे मिलियन भारतीय संविदा मजदूरों को 1834 से 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक मॉरीशस में लाया गया है जिसमें से दो तिहाई मॉरीशस में स्थाई रूप से बस गए। इस समय मॉरीशस की लगभग 68 प्रतिशत आबादी भारतीय वंश परंपरा की है।

दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते समय महात्मा गांधी द्वारा थोड़े समय के लिए यहां रूकना (29 अक्टूबर से 15 नवंबर, 1901) और अपने जहाज एस एस नौशेरा के प्रस्थान करने की प्रतीक्षा करना आज भी मॉरीशस की चेतना में समाया हुआ है। बैरिस्टर मनीलाल डाक्टर जो गांधी जी के कहने पर 1907 में मॉरीशस आए थे, ने स्वयं को संगठित करने तथा अपने राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष की नींव रखने में मॉरीशस में रहने वाले भारतीय समुदाय की मदद की। गांधी जी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मॉरीशस का राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 मार्च (जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ था) को मनाया जाता है।

राजनीतिक संबंध

12 मार्च, 1968 को मॉरीशस की आजादी के बाद, मॉरीशस के पहले प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपिता सर सिवोसागर रामगुलाम ने मॉरीशस की विदेश नीति में भारत को प्रमुख स्थान प्रदान किया। इसके बाद, मॉरीशस के उत्तराधिकारी नेताओं ने सुनिश्चित किया कि मॉरीशस की विदेश नीति के अभिविन्यास एवं गतिविधियों में भारत को महत्वपूर्ण स्थान एवं दर्जा प्राप्त हो।

उच्च स्तरीय यात्राएं द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक रही हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने 6 से 12 फरवरी, 2012 के दौरान भारत का चार दिवसीय राजकीय दौरा किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल एवं युवा, टेक्सटाइल तथा राजीव गांधी विज्ञान केंद्र में एक हाइब्रिड

प्लेनेटेरियम स्थापित करने के लिए पांच समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए। 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता से युक्त एक नए आर्थिक पैकेज तथा 20 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की गई।

मॉरीशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग ने 3 से 10 जनवरी, 2013 के दौरान भारत का राजकीय दौरा किया। वह कोच्चि में 7 से 9 जनवरी, 2013 के दौरान आयोजित 11वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, जहां उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 11 से 13 मार्च, 2013 के दौरान मॉरीशस का राजकीय दौरा किया, जिसके दौरान वह मॉरीशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्रों में सहयोग, विकलांग व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सहायता तथा पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए तीन समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम मई, 2014 में नई दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए बुलाए गए एकमात्र गैर सार्क नेता थे। अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री रामगुलाम ने आपसी हित के मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की।

माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने भारतीय संविदा श्रमिकों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ की याद में राष्ट्रीय स्तर पर समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 1 से 3 नवंबर, 2014 के दौरान मॉरीशस का दौरा किया। उनकी पहली यात्रा के अन्य घटकों में नागरिक अभिनंदन, भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के जहाजों पर स्वागत, मॉरीशस के वाणिज्य चेंबर और निवेश बोर्ड द्वारा आयोजित एक व्यवसाय बैठक तथा महात्मा गांधी संस्थान में संविदा श्रम मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन शामिल था।

मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री तथा आवास एवं भूमि मंत्री श्री शौकत अली सूधन के नेतृत्व में मॉरीशस के एक शिष्टमंडल ने 7 से 9 जनवरी, 2015 के दौरान गांधीनगर, गुजरात में 13वें पी बी डी में भाग लिया तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने 10 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में विश्व हिंदी दिवस समारोह में भी भाग लिया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मारीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 11 से 13 मार्च 2015 तक मारीशस का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्मित और भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित ओ पी वी बरकुडा भारत मारीशस के तट रक्षक बल को समर्पित किया। उन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय के निर्माण कार्य का भी श्रीगणेश किया तथा अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन में विशाल एवं जोशपूर्ण सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्रपति राजकेश्वर पूरयाग, प्रधानमंत्री सर अनिरूद जगन्नाथ तथा मारीशस के अन्य वरिष्ठ नेताओं से बहुत विस्तार से चर्चा भी की। परस्पर लाभप्रद सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में 5 करारों पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें महासागर अर्थव्यवस्था तथा परंपरागत दवा पद्धतियों पर करार शामिल है। इस यात्रा के दौरान नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता की घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री सर अनिरूद जुगन्नाथ ने तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में मॉरीशस के शिष्टमंडल के प्रमुख के रूप में अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली का दौरा किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसके बाद उन्होंने मुंबई में भारत के कारोबारी नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने दिल्ली में मॉरीशस निवेश बोर्ड की एक शाखा का भी उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति डा. अमीनाह गरीब फकीम ने 6 से 9 दिसंबर, 2015 के दौरान भारत का 4 दिवसीय राजकीय दौरा किया। उन्होंने माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, माननीया विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद का भी दौरा किया, जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के माननीय राज्यपाल से मुलाकात की तथा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दौरा किया।

भारत और मॉरीशस ने अनेक द्विपक्षीय करारों एवं एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं - दोहरा कराधान परिहार करार (डी टी ए सी - 1982), द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बी आई पी ए - 1998), हवाई सेवाओं पर एम ओ यू (2005), सूचना प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए करार (2000), जैव प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए एम ओ यू (2002), प्रत्यर्पण संधि (2003), आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एम ओ यू (2005), पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एम ओ यू (2005), आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि (2005), सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर करार (2005), जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए एम ओ यू (2005), उपभोक्ता संरक्षण एवं कानूनी मेट्रोलॉजी पर सहयोग के लिए एम ओ यू (2005), धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित वित्तीय आसूचना के आदान - प्रदान में सहयोग से संबंधित एम ओ यू (2008), नेविगेशनल चार्ट की ब्रिकी पर प्रोटोकाल; टेलीमेट्री की स्थापना, उपग्रहों के लिए ट्रैकिंग एवं

टेली-कमांड स्टेशन तथा लांच व्हीकल के लिए सहयोग पर करार तथा अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान एवं अनुप्रयोग के क्षेत्रों में सहयोग के लिए करार; कोस्टल रडार सर्विलांस सिस्टम के लिए आपूर्ति संविदा (2009), एक आफशोर पेट्रोल वाहन की आपूर्ति के लिए एम ओ यू; तटीय संकटों की शीघ्र चेतावनी पर करार (2010), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एम ओ यू (2012), खेल एवं युवा मामलों पर एम ओ यू (2012), शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम (2012), टेक्सटाइल पर एम ओ यू (2012), एक हाइब्रिड प्लेनेटोरियम स्थापित करने के लिए आर जी एस सी ट्रस्ट फंड तथा एन सी एस एम के बीच एम ओ यू (2012), चुनाव प्रबंधन एवं प्रशासन में सहयोग के लिए एम ओ यू (2013), एम एस एम ई सेक्टर में सहयोग के लिए एम ओ यू (2013), मॉरीशस प्रसारण निगम तथा प्रसार भारतीय के बीच संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एम ओ यू (2014)। इसके अलावा, 1971 से सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों पर नियमित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं।

वाणिज्यिक संबंध :

भारत मॉरीशस का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा वर्ष 2007 से मॉरीशस को माल एवं सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। वित्त वर्ष 2014-2015 में भारत ने मॉरीशस को 1.9 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के माल का निर्यात किया है तथा मॉरीशस से 21.19 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के माल का आयात किया है। मॉरीशस को भारत द्वारा जो निर्यात किया जाता है उसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। मॉरीशस की पेट्रोलियम संबंधी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल लिमिटेड (एम आर पी एल) तथा मॉरीशस राज्य व्यापार निगम के बीच तीन वर्षीय करार को जुलाई, 2013 में नवीकृत किया गया। पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा भारत द्वारा मॉरीशस को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से भेषज पदार्थ, अनाज, कॉटन, विद्युत मशीनरी, परिधान एवं कपड़े के साजो-सामान शामिल हैं। मॉरीशस द्वारा भारत को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से लोहा एवं इस्पात, मोती, बहुमूल्य / अर्ध बहुमूल्य पत्थर एवं आप्टिकल, फोटोग्राफिक तथा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं।

ज्यादातर दोहरा कराधान परिहार अभिसमय की वजह से अप्रैल 2000 से सितंबर 2015 की अवधि के दौरान मारीशस से भारत को संचयी एफ डी आई इक्विटी प्रवाह की मात्रा 91.22 बिलियन अमरीकी डालर थी जो इस अवधि में कुल एफ डी आई अंत:प्रवाह का 34 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, मॉरीशस भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) का एकल सबसे बड़ा स्रोत था तथा 2014-15 में इसने 9.03 बिलियन अमरीकी डालर का कुल एफ डी आई इक्विटी अंत:प्रवाह किया।

इस समय 8 भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मॉरीशस में काम कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा (बी ओ बी), जीवन बीमा निगम (एल आई सी) तथा न्यू इंडिया एसोरेंस कारपोरेशन (एन आई ए सी) ऐसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने प्रचालनों की स्थापना की और उसके बाद अन्य पी एस यू में मॉरीशस में अपना प्रचालन स्थापित किया जिसमें इंडिया हैंडलूम हाउस, टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), इंडियन ऑयल (मॉरीशस) लिमिटेड (आई ओ एम एल), महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लिमिटेड शामिल हैं। अपनी मुख्य गतिविधियों के अलावा, पी एस यू ने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) स्कीम के तहत मॉरीशस में विभिन्न गतिविधियों में भी योगदान दिया है।

मॉरीशस में भारत की सहायता से संचालित कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में महात्मा गांधी संस्थान, उपाध्याय प्रशिक्षण केंद्र, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, सुब्रामणियम भारती आई सेंटर, राजीव गांधी विज्ञान केंद्र तथा रवींद्रनाथ टैगोर संस्थान शामिल हैं। भारत की हाल की सहायता के प्रतिष्ठित प्रतीकों के तहत इबेन में साइबर टावर तथा स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एस वी आई सी सी) शामिल हैं।

मार्च 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत सरकार की ऋण सहायता के तहत एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेजल बरकुडा मारीशस के राष्ट्रीय तट रक्षक बल को सौंपा गया। भारत मारीशस में तथा मारीशस के ई ई जेड में संयुक्त गश्त / निगरानी अभ्यास नियमित रूप से संचालित करने के अलावा मारीशस के सशस्त्र बलों को बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण इनपुट भी प्रदान करता है। भारत ने मारीशत की राष्ट्रीय जल विज्ञानी यूनिट की स्थापना में भी सहायता प्रदान की है।

पिछले 40 वर्षों में मारीशस के अवसंरचना विकास, मानव संसाधन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण, परियोजना मूल्यांकन आदि में मदद के लिए मारीशस को अनेक ऋण सहायता प्रदान की है। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मारीशस की अपनी यात्रा के दौरान नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक नई ऋण सहायता की घोषणा की गई।

सांस्कृतिक संबंध :

फोनिक्स में स्थित इंदिरा गांधी भारतीय संस्कृति केंद्र (आई जी सी आई सी) आई सी सी आर के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, जो मार्च, 2000 से मॉरीशस में भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरा है। यह केंद्र मॉरीशस के छात्रों के लिए हिंदुस्तानी संगीत,

कथक, तबला तथा योग जैसे विषयों में कक्षाएं आयोजित करता है। मार्च 2015 में एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सी ई पी) (2015 - 2018) पर हस्ताक्षर किए गए। अगस्त 2015 से स्थानीय कला एवं संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से मॉरीशस में भारत महोत्सव 2015 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन 21 अगस्त, 2015 को माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री महेश शर्मा द्वारा किया गया।

महात्मा गांधी संस्थान (एम जी आई) को भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एवं मॉरीशस सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1970 में स्थापित किया गया। यहां संस्कृति और भारतीय दर्शन में एक आई सी सी आर पीठ भी है। रवींद्रनाथ टैगोर संस्थान को 2000 में भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं पर एक अध्ययन केंद्र के रूप में भारत सरकार की सहायता से स्थापित किया गया। मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय भी है। योग तथा स्वास्थ्य की परंपरागत भारतीय पद्धतियां (आयुष) मॉरीशस की आम जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश में भव्य पैमाने पर मनाया जाएगा। स्थानीय सामाजिक - सांस्कृतिक संगठनों एवं भाषा संघों के एक सक्रिय नेटवर्क से जीवंत जन दर जन संपर्कों की मजबूती एवं महत्व और बढ़ रहा है।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) 1964 में अपने शुरूआत के समय से ही भारत का एक फ्लैगशिप क्षमता निर्माण कार्यक्रम रहा है तथा मॉरीशस के साथ भारत की विकास साझेदारी में एक मजबूत ब्रांड नाम प्राप्त कर लिया है। मॉरीशस भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के सबसे बड़े लाभार्थी देशों में से एक है। मॉरीशस के नागरिकों ने भारत की संस्थाओं में सिविल एवं रक्षा से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर भारत द्वारा प्रस्तावित भारी संख्या में छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया है।

अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना का उद्घाटन मॉरीशस में 26 फरवरी, 2009 को किया गया जिसमें एक उपग्रह एवं फाइबर आप्टिक नेटवर्क के माध्यम से इसे अफ्रीका के अन्य देशों एवं भारत से जोड़ा। इससे शिक्षा एवं स्वास्थ्य देख-रेख में भारत की विशेषज्ञता को साझा करने से मॉरीशस को लाभ हुआ है। सभी तीन मोड - वी वी आई पी, टेलीमेडिसीन एवं टेली-एजुकेशन - इस समय सक्रिय हैं।

भारत में उच्च शिक्षा के लिए मॉरीशस के छात्रों को हर साल लगभग 100 आई सी सी आर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। स्व-वित्त पोषण के आधार पर हर साल भारतीय विश्वविद्यालयों में मॉरीशस के लगभग 200 अन्य छात्र नामांकन कराते हैं। विदेशी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई करने वाले मॉरीशस के छात्रों की संख्या की दृष्टि से भारत चौथे स्थान पर है।

भारतीय समुदाय

मारीशस में लगभग 11 हजार भारतीय नागरिक हैं। लगभग 750 ओ सी आई कार्ड धारक और लगभग 3500 पी आई ओ कार्ड धारक हैं। भारत से पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए मॉरीशस सरकार ने अक्टूबर, 2004 में, भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री व्यवस्था शुरू की थी जिसमें 60 दिन तक की अवधि के लिए मॉरीशस का दौरा करने वाले भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं होती है, बशर्ते वे अपने प्रवास को कवर करने के लिए वे पर्याप्त धन प्रदर्शित कर सकें। भारत का दौरा करने वाले मॉरीशस के नागरिक मुफ्त ई-टूरिस्ट वीजा के पात्र हैं।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय उच्चायोग, पोर्ट लुइस की वेबसाइट :
http://indiahighcom-mauritius.org/

भारतीय उच्चायोग, पोर्ट लुइस का फेसबुक पृष्ठ :
https://www.facebook.com/indiainmauritius

इंडिया ग्लोबल : ए आर आई - एफ एम गोल्ड जो भारत तथा मॉरीशस संबंधों पर आधारित कार्यक्रम है :
http://www.youtube.com/watch?v=L8oyjsa4PYA

****

जनवरी, 2016